विचार बिन्दु

ठोकरें केवल धूल ही उड़ाती हैं, फसलें नहीं उगाती। –टैगोर

मणिपुर की घटना शर्मनाक और उस पर हो रही राजनीति भी शर्मनाक

मणिपुर में जिस प्रकार से सेंकड़ों लोगों की भीड़ ने आदिवासियों की महिलाओं को पुलिस से छुड़ा कर, निर्वस्त्र कर उनकी परेड एवं उनकी देह के साथ दरिंदगी की, उससे पूरा देश शर्मसार हुआ है। इससे पूरी दुनिया में भारत की छवि को धक्का लगा है। यह घटना तो 4 मई 2023 की है किंतु इसका वीडियो अभी हाल ही में वाइरल हुआ है। वीडियो में जिस प्रकार की हैवानियत महिलाओं के शरीर के साथ की गई, उससे मानवता भी शर्मसार हुई है। हमारी प्राचीन एवं समृद्ध सभ्यता जिस पर हम गर्व करते रहे हैं वह भी कलंकित हुई है। जहां नारी की पूजा की बात शास्त्रों में की गई है वहां नारी के साथ इस तरह सार्वजनिक अभद्रता अकल्पनीय है।

मैती समुदाय को अनुसूचित जाति में सम्मिलित कराने हेतु गौहाटी उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध 3 मई को एक विशाल मार्च, नागा कुकी आदिवासियों द्वारा आयोजित किया गया। उपरोक्त घटना 4 मई को हुई जिसकी एफ आई आर 18 मई को दर्ज हुई। इस वीडियो के वायरल होने तक राज्य सरकार ने किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की। इन्टरनेट बंद होने के कारण इसके बारे में देश को जानकारी नहीं हुई किन्तु यह असंभव है कि राज्य सरकार एवं भारत सरकार के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी ना हो। पूरी जानकारी होने के बावजूद भी राज्य सरकार, जिस पर महिलाओं की इज्जत की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, वही यदि महिलाओं की इज्जत को तार-तार करने में अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार हो जाए तो इससे अधिक शर्म की बात किसी भी देश के लिए नहीं हो सकती।

प्रधानमंत्री जो हर छोटी बड़ी बात पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर देश को संबोधित करते रहे हैं, ने भी मणिपुर की हिंसा, जिसमें 150 के लगभग जाने जा चुकी है, उसके बारे में 78 दिन तक एक शब्द नहीं बोले। प्रधानमंत्री का पहला वक्तव्य मणिपुर पर तब आया, जब माननीय उच्च न्यायालय ने इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए निर्देश दिए कि यदि एक सप्ताह में सरकारों ने कुछ कार्यवाही नहीं की तो उच्चतम न्यायालय स्वयं कुछ कार्रवाई करने हेतु बाध्य होगा। प्रधानमंत्री ने इस घटना पर 78 दिन बाद क्रोध एवं शोक व्यक्त किया, किंतु ऐसा करते समय उन्होंने राजस्थान, छत्तीसगढ़ की घटनाओं को भी मणिपुर से जोड़ते हुए एक प्रकार से इस घटना की गंभीरता को हल्का ही करने का प्रयास किया है। साथ ही इस घड़ी में भी इस विषय पर राजनीति करने से नहीं चूके। मुख्य न्यायाधीश ने स्वत: संज्ञान लेते हुए यह कहा कि इस प्रकार की स्थिति अस्वीकार्य है। जब से उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इस घटना का संज्ञान लिया है, भाजपा की ट्रॉल सेना ने मुख्य न्यायाधीश के अपशब्दों के प्रति की झड़ी लगा दी है।

मणिपुर के मुख्यमंत्री का बयान तो अत्यंत दुखद और आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा कि यहां तो सैंकड़ों ऐसी घटनाएँ हुई हैं, एक घटना के पीछे क्यों पड़े हैं? मणिपुर के राज्यपाल ने सार्वजनिक वक्तव्य में यह कहा कि मणिपुर में स्थिति बेकाबू होने की जानकारी उन्होंने समय पर ऊपर तक, अर्थात गृह मंत्रालय एवं प्रधानमंत्री तक, पहुंचा दी थी। इस घटना को दबाए रखना एवं इस पर कोई कार्यवाही ना करना राज्य द्वारा इस घटना के प्रति मौन सहमति ही माना जाएगा।

इसके बावजूद भी अभी तक राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया है। मणिपुर में इस समय जो स्थितियां हैं वह गृह युद्ध की तरह हैं। जहां राज्य के पुलिस भी हिंसा में एक पक्ष के रूप में कार्य कर रही है। यदि ऐसा नहीं होता तो जिस प्रकार महिलाओं को पुलिस के कब्जे से छुड़ा लिया गया और पुलिस द्वारा उन्हें बचाने के लिए बल प्रयोग तक न करना क्या कहा जाएगा? यह कैसी विडंबना है कि ऐसी जघन्य घटना की अन्य घटनाओं से तुलना कर इसे हल्का किया जा रहा है। कई लोग तो इसका औचित्य ढूंढने का प्रयास भी कर रहे हैं। दलों की राजनीति अपनी जगह है किंतु क्या महिलाओं की इज्जत राजनीति के बलि चढ़ा दी जाएगी? अपराध अन्य राज्यों में भी हुए, हैं किंतु राज्य की पुलिस के समक्ष सैकड़ों लोगों के सामने इस प्रकार का वीभत्स व्यावहार महिलाओं के साथ किया जाए, वह अक्षम्य है।

प्रधानमंत्री जी कई बार यह कह चुके हैं कि उनके लिए सर्वोपरि राष्ट्र है उसके बाद दल एवं उसके बाद व्यक्ति। इस प्रकार की आदर्श बात करने वाले प्रधानमंत्री द्वारा केवल दलगत राजनीति के कारण कुछ ठोस कार्यवाही न करना विडंबना ही कहा जाएगा। जिस समय मणिपुर जातिगत हिंसा की आग में झुलस रहा था, प्रधानमंत्री ने मणिपुर का दौरा करने और मणिपुर के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करने के स्थान पर अपने लिए फ्रांस में सम्मान प्राप्त करना और अमेरिका में अप्रवासी भारतीयों के समारोहों में सम्मिलित होना अधिक उपयुक्त माना।

मणिपुर के मुख्यमंत्री का बयान तो अत्यंत दुखद और आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा कि यहां तो सैंकड़ों ऐसी घटनाएँ हुई हैं, एक घटना के पीछे क्यों पड़े हैं? मणिपुर के राज्यपाल ने सार्वजनिक वक्तव्य में यह कहा कि मणिपुर में स्थिति बेकाबू होने की जानकारी उन्होंने समय पर ऊपर तक, अर्थात गृह मंत्रालय एवं प्रधानमंत्री तक, पहुंचा दी थी।

भारतीय जनता पार्टी की ट्रॉलआर्मी निरंतर सोशल मीडिया के माध्यम से यह बताने का प्रयास कर रही है कि कैसे मणिपुर में ईसाइयों का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है एवं हिंदुओं की स्थिति कमजोर होती जा रही है। क्या इस प्रकार से महिलाओं को बेइज्जत करके ईसाइयों की बढ़ती आबादी का दुष्परिणाम कुछ महिलाओं को भोगना पड़ेगा? वे अपने सोशल मीडिया की पोस्ट के माध्यम से इस आंदोलन को अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। यह समय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाने का नहीं है। अभी तो इस प्रदेश की महिलाओं की गरिमा का प्रश्न है। ऐसी सरकार को शासन में रहने का हक नहीं है जो इस प्रकार की घटनाओं का औचित्य ढूंढने का प्रयास करें।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी सार्वजनिक रूप से कई बार गरीब आदिवासी जनता के प्रताड़ित होने की बात करती रहे हैं और इस बारे में उन्होंने उच्चतम न्यायालय तक को आगाह किया है। इस घटना के सम्बन्ध में उनका मौन समझ से परे है।

एक और जहां भारत को विश्व गुरु बताने और बनाने की बात की जा रही है, वहीं इस प्रकार की घटनाएं हमें शर्मिंदगी से भर देती हैं। इक्का दुक्का घटना कहीं पर होना अलग बात है। उनमें लिप्त अपराधियों को कार्रवाई करके सजा दी जा सकती है, किंतु इस प्रकार की सार्वजनिक रूप से होने वाली घटना का संज्ञान भी सरकारों द्वारा 2 माह तक नहीं लिया जाना किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उन आदिवासी पिता और पुत्र पर क्या बीती होगी जिन्हें अपनी बेटी और बहन की इज़्ज़त बचाने के प्रयास के कारण भीड़ ने पुलिस के समक्ष गोली मार दी।

3 मई से चल रही विभिन्न हिंसक घटनाओं में पुलिस से विभिन्न प्रकार के हथियार छीन लिए गए हैं। इन्हीं हथियारों का उपयोग एक दूसरे समुदाय के विरुद्ध किया जा रहा है। इस प्रकार के चुने गए हथियारों में, न केवल राइफल एवं अन्य हथियार हैं अपितु एल एम जी तक हैँ। इन्हें ज़ब्त करने का अभियान अभी तक नहीं चलाया गया है।

यह सही है कि मैती और कुकी आदिवासियों में विवाद और संघर्ष बहुत पुराना है। राज्य प्रशासन में लोग दोनों समुदाय से हैं किन्तु वर्चस्व मैती लोगों का है। प्रशासन चाहे वह भारत सरकार का हो अथवा राज्य सरकार का, उनमें कार्यरत अधिकारी किसी भी जाति या धर्म के क्यों ना हो, उनका प्रथम दायित्व संविधान के प्रति ही होना चाहिए। उनका कर्तव्य है कि वह सभी नागरिकों को समान दृष्टि से देखते हुए उनकी गरिमा की रक्षा करें। आदिवासी महिलाओं के साथ जो हुआ वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है किन्तु वह पुलिस की उपस्थिति में हुआ, उससे अधिकारियों की मिलीभगत का संदेह तो होता ही है। इन अधिकारियों ने अपना कर्तव्य नहीं निभाने के साथ ही इंसानियत भी ताक पर रख दी।जिस जाति या धर्म के अधिकारी प्रशासन में अधिक होंगे क्या वे केवल अन्य जाति और धर्म के लोगों का दमन करने का ही कार्य करेंगे? जर्मनी में हिटलर की नाजी सेना ने यहूदियों के साथ कुछ इसी तरह का व्यवहार किया था जैसा कुकीज आदिवासियों के साथ हुआ। जब जनता के एक वर्ग के प्रति दुर्व्यवहार और प्रताड़ना को प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से राजकीय संरक्षण प्राप्त हो जाए तो स्थिति किसी भी हद तक गिर सकती है, हमने मणिपुर के प्रकरण में देखा है।

अब जबकि उच्चतम न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया है तो यह अपेक्षा की जा सकती है न्यायालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो और राज्य के इंटेलिजेंस विभाग से पूरी घटनाओं की पृष्ठभूमि की जानकारी लेगा और इसके लिए जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों को तत्काल पद से मुक्त करने के लिए निर्देश जारी करेगा। साथ ही ऐसे अक्षम मुख्यमंत्री को तत्काल बर्खास्त करने के निर्देश भी जारी किए जाएंगे। यदि उच्चतम न्यायालय ने भी कोई प्रभावी कार्यवाई नहीं की तो जनता का भरोसा जो उच्चतम न्यायालय में बना हुआ है, वह ध्वस्त हो जाएगा।

भारत सरकार मणिपुर के निवासियों की वास्तव में चिंता करती है और उनकी समस्याओं को सुलझाने के प्रति संवेदनशील है, इसका प्रमाण तो आने वाले भारत सरकार के कदमों से ही तय होगा। यदि कुछ नहीं किया गया और उच्चतम न्यायालय भी सरकार को समुचित कार्यवाही करने हेतु बाध्य नहीं कर पाया तो फिर मणिपुर तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति क्या होगी, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। हम नागरिक के रूप में इस समय मणिपुर के निवासियों के साथ अपनी पूरी एकजुटता प्रदर्शित करते हुए सरकार से यही मांग करते हैं कि वह अब तक हुए अन्याय को दूर करने के लिए अत्यंत कठोर कदम उठाए जिससे सभी समुदाय के लोगों में विश्वास बने। जिन राजनेताओं द्वारा मणिपुर की हिंसा की तुलना अन्य राज्यों की घटनाओं से की जा रही है वह दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि मणिपुर में लगभग 3 माह से हत्या, बलात्कार आदि की घटनाएं जारी हैं जैसा कि स्वयं मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल तक ने स्वीकार किया है।

भाजपा के इस कथन में सच्चाई हो सकती है कि वीडियो को संसद सत्र के प्रारंभ होने के साथ ही वाईरल करना राजनीति से प्रेरित है। केंद्र सरकार ट्विटर पर कार्रवाई करने की बात कर रही है। यह तो वैसा ही है जैसे संदेश लाने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, किंतु जिस व्यक्ति ने अत्याचार किया है उस पर कोई कार्यवाही ना हो।

आइए, हम सब मिलकर मणिपुर वासियों के प्रति संवेदना के साथ इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े रहें और उन्हें न्याय दिलाने हेतु दबाव बनाएं, जैसा कि निर्भया कांड के समय हुआ था जब पूरा देश एक साथ उठ खड़ा हुआ था। महिलाओं के साथ इस प्रकार की वीभत्स घटनाओं पर भी नागरिकों का खून नहीं खोलता है तो फिर उनकी रगों में शायद खून नहीं पानी है। केंद्र सरकार से यह भी अपेक्षा है कि बिना तकनीकि कारणों में उलझे, राजनीति से ऊपर उठकर इस पर संसद में तत्काल चर्चा कराए ताकि संसद के सदस्यों की एक आवाज मणिपुर तक पहुंचे कि पूरा देश मणिपुर के लोगों के साथ है।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

मतदाता उपभोक्ता नहीं, वह सत्ता में बराबर का भागीदार है

राजेन्द्र जोशी

वैसे तो भारत में वर्ष भर चुनावी मौसम बना रहता है। परन्तु विधानसभा चुनावों के दौरान मतदाता उपभोक्ता का स्थान ले लेते हैं। सरकारें उपभोक्ताओं को बड़े- बड़े वादे करने लगती है और विपक्षी पार्टियां सत्ता में आने के लिए वर्तमान सत्ता पर चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार काम नहीं करने का आरोप लगाकर खुद सत्ता में आने का भरसक कोशिश करती है।

जिस प्रकार कम्पनियाँ उपभोक्ताओं को लालच देती है, नीचे छोटे अक्षरों में लिखा होता है शर्ते लागू। उसी प्रकार राजनैतिक पार्टियां भीतर छुपा हुआ एजेंडा भी रखती है। कंपनियां अपने उपभोक्ताओं को जीवन भर लाभ देने का काम नहीं करती बल्कि वह किसी एक प्रोडक्ट पर उस माल की उपलब्धता तक लालच देती है। ठीक उसी प्रकार राजनीतिक पार्टियां कभी कहती है कि लोन माफ कर देंगे, कभी कहती है कि लाडली को स्वाभिमान राशि देंगे, कभी कहती है कि एक साल के लिए चिरंजीवी योजना में शामिल करेंगे। परंतु सरकारें यह भरोसा नहीं देती कि यह योजना स्थाई रहेगी।

राजनैतिक दल चुनाव घोषणा-पत्र में पेट्रोल डीजल के दाम घटानें, यह वादा नहीं करती कि किसी भी कीमत पर सरकार दाम बढ़ने नहीं देगी। जरूरी दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं की राशि स्थाई रूप से कम की जाएगी, यह किसी भी पार्टी में लाभ देने की योजना में शामिल नहीं होता। जिस प्रकार उपभोक्ताओं को बड़े लालच दिए जाते हैं, उसी प्रकार राजनैतिक पार्टियां बड़े वादे करके सत्ता के लिए लालायित हैं। जरूरत इस बात की है की आम आवाम को उपभोक्ता ना बनाया जाए, बाजार की वस्तु ना समझा जाए।

मतदाता ही स्थाई है उसको मतदाता के रूप में समझा जाना चाहिए। यहां यह बात विचारणीय है की राजनैतिक पार्टियां अलग-अलग विधानसभा एवं अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग वादे करती है। राष्ट्रीय पार्टियों को चाहिए भारत में क्षेत्रीय उपभोक्ता नहीं बल्कि भारतीय मतदाता समझते हुए समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। जरूरी यह भी है कि जिस तरह राजनैतिक पार्टियां जिताऊ उम्मीदवार के लिए सर्वे करवाती है उसी प्रकार चुनाव घोषणा पत्र बनाने से पूर्व घर-घर आवश्यकताओं की जानकारी की जानी चाहिए।

उपभोक्ता की भांति उससे भी अधिक बढ़-चढ़कर ढेरों उपहार देने का वादा राजनैतिक दल कर बैठते है। लोकतंत्र में सता का चरित्र अब एक जैसा होने लगा है। इन दिनो राजस्थान-छतीसगढ-मध्य प्रदेश में दैनिक समाचार पत्रों के फ्रंट पेज पर रोज खातों में राशि डालने सहित अनेक लोक-लुभावन लालच देकर चुनावी शंखनाद हो चुका है। राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को यह भरोसा दिला रही है कि हम सितंबर तक उम्मीदवारों के नाम तय कर देंगे, एक भी राजनैतिक दल यह बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही कि हम चुनाव घोषणा पत्र अगस्त-सितंबर सितंबर में जारी कर देंगे, जिस तरह लोकलुभावन घोषणाएं समाचार पत्रों में की जा रही है, राजनीतिक दलों को चाहिए कि वह अपने घोषणा पत्र भी चार माह पूर्व इसी प्रकार समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाएं। मतदाताओं को बाजारू वस्तु समझते हुए उपभोक्ता ना बनाया जाए, उसे मतदाता ही रहने दिया जाए। मतदाता सत्ता में बराबर भागीदार है।

लेखक हिन्दी-राजस्थानी भाषा के वरिष्ठ साहित्यकार है।

–राजेन्द्र जोशी,
कवि-कथाकार

बी.पी.एल. परिवार के तीन बच्चों को एक बार भी नहीं मिली छात्रवृत्ति

- **चूरू के रिड़खला गांव का है बीपीएल परिवार**
- **साढ़े चार साल में एक बार भी नहीं मिली छात्रवृत्ति, हर वर्ष आवेदन पत्र भी भरे जाते हैं**

चूरू, (कासं)। निकटवर्ती गांव रिड़खला के एक बीपीएल परिवार के तीन बच्चों में से आज तक एक को भी छात्रवृति नहीं मिली है। जबकि उनके हर वर्ष आवेदन पत्र भी भरे जाते हैं। आज यहां रीको कार्यालय के पास स्थित ग्रामीण बैंक में अपनी पुत्री सुनिता का खाता खुलवाने के लिए आई मैना देवी पत्नी महेन्द्र कुमार ने बताया कि सुनिता कक्षा 6 में राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय रिड़खला में पढ़ती है।

गुरुजी ने आज का आज खाता खुलवाने के लिए कहा है। बैंक वाले कह रहे हैं कि 10 वर्ष उम्र होने के बाद ही सुनिता का खाता खुलेगा। संयुक्त खाता खुलवाने के एक हजार रुपए मांग रहे हैं। सुनिता का छात्रवृति के लिए आवेदन करना है। उसके खाते में ही आएगी बताते हैं।

मैना देवी ने बताया कि उनका परिवार बीपीएल की श्रेणी में है। उसके तीन लड़के 12वीं, 9वीं और 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। किसी को भी आज तक एक रुपए की छात्रवृति नहीं मिली है। सबका बैंक में खाता भी है। खाते में रुपए आज तक नहीं आए हैं। अब सुनिता का फार्म भरकर और देख लेते हैं। कुल मिलाकर रिड़खला गांव में इस बीपीएल परिवार के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलना सरकार और यहां बड़े-बड़े दावे करने वाले अधिकारियों की सतर्कता की पोल खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने बताया कि कोई कारण भी नहीं बता रहे हैं।

सब कागजात एकदम सही है। आज भी बैंक में खाता नहीं खुल पाया और समय और रुपए का नुकसान हो गया। खेत में निनाण छोड़कर यहां बैंक में आई थी। इस संबंध में प्रशासन की चुप्पी से लगता है कि उन्होंने गहलोत सरकार के विदाई समारोह की तैयारी शुरू कर दी है।

बिना लोको पायलट चल पड़ा मालगाड़ी का इंजन

सूरतगढ़, (निसं)। सुपर थर्मल पावर प्लांट में रविवार को 1500 मेगावाट की सब क्रिटिकल थर्मल परियोजना में कोल रैक लेने आया एक लोको (रेल इंजन) बिना पायलट के ही करीब दो किलोमीटर से ज्यादा दौड़ते हुए 1320 मेगावाट की सुपरक्रिटिकल तापीय परियोजना में पहुंच गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार परियोजना के वैगन टिपलर नंबर 3 से खाली कोल रैक लेने आए सूरतगढ़ थर्मल के इंजन को खड़ा कर लोको पायलट और पॉइंटमैन आसपास कहीं चले गए। इसी दौरान इंजन अपने आप चलने लगा। कुछ समय बाद लोको पायलट और पॉइंटमैन के आने पर उन्होंने इंजिन को दूर जाते देखा। इस संबंध में अधिकारियों को सूचित किया तब तक रेलवे इंजन करीब 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय कर चुका था। जिसके बाद सुपरक्रिटिकल परियोजना के लोको पायलट ने सूचना के बाद इस चलते इंजन में चढ़कर उसे रोका।

इस मामले को लेकर बिजली उत्पादन इंटक के प्रदेश महामंत्री श्याम सुंदर शर्मा ने इस घटना को एक गंभीर लापरवाही बताया।

अध्यापकों की कमी से नाराज ग्रामीणों ने स्कूल गेट पर ताला लगाया

ग्रामीणों ने ताला लगाकर प्रदर्शन किया और धरना भी दिया

- **सूचना पर उप सरपंच मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की**
- **जमकर की नारेबाजी, लंबे समय से टीचर के 4 पद खाली है**

टोंक, (निसं)। दूनी तहसील के खरोई गांव के स्कूल में अध्यापकों की कमी से नाराज ग्रामीणों ने सोमवार सुबह स्कूल के ताला लगा दिया। ग्रामीणों ने राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल के गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान करीब आधा घंटा तक धरना भी दिया। सूचना मिलने पर उप सरपंच मौके पर पहुंचे और हेड मास्टर के साथ मिलकर ग्रामीणों से समझाइश की। डेढ़ घंटे बाद ग्रामीणों ने स्कूल का ताला खोल दिया।

जानकारी के अनुसार राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में 8 शिक्षकों के मुकाबले 4 शिक्षक नियुक्त हैं। शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई काफी बाधित हो रही है। इसको लेकर ग्रामीणों ने भी सरकार से लेकर प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन अभी तक भी टीचर नहीं लगे। इससे परेशान होकर ग्रामीणों ने सोमवार सुबह करीब 7.30 बजे स्कूल पर ताला लगा दिया और जमकर नारेबाजी की। इसके बाद ग्रामीण धरने पर बैठ गए। जानकारी मिलने पर उप सरपंच प्रधान लाल मीणा भी मौके पर पहुंचे और हेड मास्टर मुकेश पारीक के साथ मिलकर ग्रामीणों से समझाइश की। उप सरपंच ने बताया कि जल्द ही शिक्षक लगाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इससे संतुष्ट होने पर ग्रामीणों ने स्कूल के गेट से करीब नौ बजे ताला खोल दिया।

ग्रामीण भारत में शिक्षा की अलख जगा रहा अंत्योदय फाउण्डेशन

पन्नालाल मेघवाल

स्वयं का दर्द महसूस करना जीवित होने का प्रमाण है। दूसरों का दु:ख महसूस करना इंसान होने का प्रमाण है। इस युक्ति को चरितार्थ करते भादसोड़ा, चित्तौड़गढ, राजस्थान के मूल निवासी एवं पूर्व मुख्य सचिव, राजस्थान पद्मश्री मीठालाल जी मेहता के अनुज श्री महेंद्र मेहता, हाल मुकाम मुंबई ने आईआईटी, दिल्ली से इंजीनियरिंग की। एक वर्ष तक अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर पद पर कार्य किया। अग्रज मीठालालजी मेहता और पिताजी मोतीलालजी मेहता के सामाजिक विचारों और कार्यों से प्रभावित होकर समाज सेवा और देश सेवा का जज्बा लेकर पुन: स्वदेश लौटे। यहां आकर आईटी सेक्टर में अपना खुद का व्यवसाय प्रारंभ किया। समाज सेवा की शुरुआत करते हुए वर्ष 2019 में अंत्योदय फाउंडेशन नाम से संस्था बनाई। आरंभ में खिलौना बैंक योजना की शुरुआत की।

खिलौना बालक की पहली पुस्तक होता है, जिससे वह उसके रंग, रूप, आकर, गति, आकृति आदि की समझ बनाता है। संस्था ने देश के एक हजार एक सौ से अधिक विभिन्न सरकारी विद्यालयों में खिलौना बैंक स्थापित किए। इन विद्यालयों में कुछ शैक्षिक, सह शैक्षिक खिलौने जिसमें अल्फाबेट मैगनेटिक बोर्ड, मैथ बिल्डर, पार्ट्स ऑफ बॉडी, इंटेली किड्स, एनिमल जिग्सा पजल, टेनिस बॉल, नेलकर, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा पुस्तिकाएं, एनएमएमएस परीक्षा तैयारी पुस्तिकाएं इत्यादि सेट नि:शुल्क उपलब्ध कराकर अनुकरणीय कार्य किया। परिणाम स्वरुप बच्चे अपना मानसिक और शारीरिक विकास कर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़कर एक सुनहरे भारत के निर्माण हेतु आगे बढ़ रहे हैं।

अंत्योदय फाउंडेशन के संस्थापक श्री महेंद्र मेहता ने सामाजिक कार्य करते हुए जब विभिन्न गांवों के बच्चों को तंग कपड़ों और फटे हाल देखा तो उनका दर्द महसूस करते हुए अपने सीए मित्र श्री संजय बोर्डिया के साथ मिलकर मुंबई में एक कपड़ा बैंक की स्थापना की। संस्था के कार्यकर्ताओं ने मुंबई के अलग-अलग हिस्सों से नए-पुराने कपड़े एकत्रित किए। संस्था ने अब तक सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं और जरुरतमंद लोगों को लगभग पांच लाख कपड़े उपलब्ध कराकर सराहनीय मानव सेवा की है। फाउंडेशन के संस्थापक ने समाज सेवा कार्य के दौरान महसूस किया कि अक्सर विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है। ग्रामीण बच्चे तकनीकी से कोसों दूर हैं। उन्होंने पुत्र श्री अंकित मेहता के साथ मिलकर स्मार्ट क्लास रूम खोलने की योजना बनाई। उन्होंने अंत्योदय फाउंडेशन के तहत देश के 80 सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम स्थापित किए। इन विद्यालयों में स्मार्ट एलईडी सेट, प्रोजेक्टर, साउंड सिस्टम सुलभ करवाए। जिससे ग्रामीण बच्चों ने तकनीकी से जुड़कर ऑनलाइन कंटेन से अपना सेलेबस पढ़कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण किया।

अंत्योदय फाउंडेशन द्वारा ग्रामीण व सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा तथा एनएमएमएस परीक्षा की तैयारी हेतु प्रेरित कर नि:शुल्क कोचिंग क्लास के माध्यम से बच्चों को बेहतर शिक्षा हेतु तैयार किया जा रहा है। अब तक इन कक्षाओं के माध्यम से 190 छात्र-छात्राओं का एनएमएमएस परीक्षा में चयन हुआ है।

फाउंडेशन द्वारा पढ़ाई छोड़ चुकी बालिकाओं और महिलाओं को संबल देने के क्रम में नि:शुल्क कोचिंग क्लास और नि:शुल्क सिलाई केंद्र स्थापित कर इनके हुनर को निखारने का अनुकरणीय कार्य किया जा रहा है। अंत्योदय फाउंडेशन द्वारा स्कूली दिव्यांग छात्र-छात्राओं को व्हीलचेयर एवं गावों के बुजुर्ग महिला-पुरूष जो चलने में अक्षम है, उन्हें वाकिंग स्टिक्स और वॉकर भेंट कर सहारा दिया जा रहा है। फाउंडेशन के संस्थापक श्री महेंद्र मेहता और टीम के सदस्य श्री संजय बोर्डिया, श्री सुरेंद्र लावटी, श्रीमती रीना बोर्डिया एवं श्री प्रह्लाद कुलकर्णी आज के भौतिक और सीमित सोच रखने वाले समाज में असहाय और साधनों से वंचित लोगों के लिए आशा की किरण बनकर काम कर रहे हैं। समाज के कमजोर पक्ष को सुदृढ़ कर उनके समुचित विकास के लिए तन-मन- धन से पूर्णत: समर्पित हैं। समाज का अभिजात्य वर्ग अगर इसी तरह अंत्योदय की भावना से काम करे तो भारत को सोने की चिड़िया बनते देर नहीं लगेगी। अंत्योदय फाउंडेशन का काम इस बात का उदाहरण है कि कैसे करुणा और समर्पण समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इस दृष्टि से अंत्योदय फाउंडेशन अपने नाम को चरितार्थ करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे संतु निरामया के वैदिक दर्शन को अमल में लाने का प्रशंसनीय कार्य किया है।

–पन्नालाल मेघवाल, वरिष्ठ लेखक एवं स्वतंत्र पत्रकार

राशिफल मंगलवार 25 जुलाई, 2023

पंडित अनिल शर्मा

प्र. सावन मास (अधिक), शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2080, चित्रा नक्षत्र रात्रि 12:03 तक, सिद्ध योग दिन 3:01 तक, वणिज करण दिन 3:09 तक, चन्द्रमा आज दिन 11:13 से तुला राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कर्क, चन्द्रमा-कन्या, मंगल-सिंह, बुध-सिंह, गुरू-मेष, शुक्र-सिंह, शनि-कुम्भ, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

आज द्विपुष्कर योग और राजयोग सूर्योदय से दिन 3:09 तक है। आज भद्रा दिन 3:09 से रात्रि 3:31 तक है। आज मंगला गौरी पूजा है।

सर्वश्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:12 से 10:53 तक, लाभ-अमृत 10:53 से 2:14 तक, शुभ 3:54 से 5:35 तक।

राहूकाल: 3:10 से 4:30 तक। सूर्योदय 5:51, सूर्यास्त 7:15

मेष

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में प्रसन्नता-हर्षोल्लास का माहौल रहेगा। सामूहिक प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष

मित्रों/रिश्तेदारों से चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त कार्य व्यवस्थित होने लगेंगे। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन

परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। रचनात्मक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

कर्क

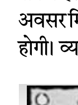

घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है।

सिंह

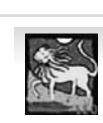

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी बनी रहेगी।

कन्या

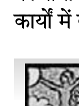

आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी और व्यावसायिक व्यक्तिगत खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी।

तुला

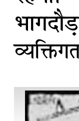

अपने अति आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक

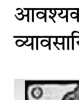

धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। धार्मिक कार्यों पर धन खर्च हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।

धनु

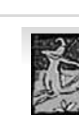

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी।

मकर

व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। आवश्यक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

कुंभ

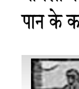

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। चलते कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

मीन

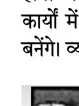

अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। यात्रा में परेशानी हो सकती है।